



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 27 नवम्बर, 2010 / 6 अग्रहायण, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०-III)

अधिसूचना

शिमला—2, 24 नवम्बर, 2010

संख्या: फीईआर (एफी)-सी-ए (3)-४ / 2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चालक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबन्ध—"I" के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्ति नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों के लिए लागू होंगे :

परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय—समय पर जारी चालक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती की पद्धति प्रवृत्त नहीं रहेगी :

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पर (एफी) सी—बी (19)—2 / 98 तारीख 4 जनवरी, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवाएं (चालक) का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप—नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (कार्मिक) ।

उपांच्छा—I'

हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन विभागों में चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—चालक

2. पदों की संख्या.—जैसी सम्बद्ध विभाग में सरकार द्वारा समय—समय पर मंजूर की गई है/की जाएगी ।

3. वर्गीकरण.—वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.—I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :

पे बैन्ड : 5910—20200 ₹

जमा ग्रेड पे 2000/- ₹

II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाः

7910/- ₹ स्तम्भ संख्या: 15—क में दिए गए व्यौरे के अनुसार ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.—अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात् वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—(क)
अनिवार्य अर्हता : (1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्था से दसवीं पास या इसके समतुल्य हो।

(2) पहाड़ी स्थानों पर हल्के/भारी वाहन चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञाप्ति धारक हो।

(ख) वांछनीय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रुद्धियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।—आयु : लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हता : हाँ, जैसा उपर्युक्त स्तम्भ संख्या—7 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।—दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित करणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता—(1) यथास्थिति अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

(2) बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा या ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।—क्लीनर—एवं—परिचालक/हैल्पर में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या सम्बद्ध ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए कलीनर-एवं-परिचालकों/हैल्परों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काड़र) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच—बागड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काड़र में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैकनीकल सर्विसेज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसेज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।—जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा।—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और अभ्यर्थी के गाड़ी चलाने एवं रख-रखाव कौशल हेतु व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त मोटरयान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और प्रबन्धक/फोरमैन, हिमाचल पथ परिवहन निगम में से कम से कम दो व्यक्तियों से गठित होगी। व्यावहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।—इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन ————— (विभाग का नाम) में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि को बढ़ाने/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि उस वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्ति किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण सन्तोषजनक रहा है। केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में न आना :

सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यारे दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित

करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ :

संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को 7910/- ₹ की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- ₹ की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी :

सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7910/- ₹ की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/- ₹ (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध सुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0,—एस0आर0, छटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—‘ख’

चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य _____(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/ श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य, (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि को बढ़ाने/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा को बढ़ाया/नवीकृत किया जा सकेगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7910/- ₹ प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त चालक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त चालक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चालक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उस अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ₹५००००००/०० रुपये/०० रुपये/०० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP) C-A (3)4/2010 dated 24-11-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL (AP-III) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 24th November, 2010

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh is pleased to make the Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver (Class-III, Non-Gazetted, Ministerial Services) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Department of State of Himachal Pradesh:

Provided that the method of direct recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Driver under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:

Provided that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/High Court of H.P.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Class-III Services (Driver) notified *vide* this Department Notification No. No. Per (AP) C-B (19)-2/98 dated: 04.01.1999 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Personnel).

Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver, Class-III (Non-Gazetted) in the Departments under Government of Himachal Pradesh

- 1. Name of Post.**—Driver.
- 2. Number of Posts.**—As sanctioned and may be sanctioned by the Govt. from time to time in the Department concerned.
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services).
- 4. Scale of Pay.**— (I) Pay band for regular incumbents:
PB-2 Rs. 5910- 20200+2000 Grade Pay.
(II) Emoluments for Contract Employees: Rs. 7910/- as per details given in Col. 15-A.
- 5. Whether “Selection” Post or “Non- Selection” Post.**—Non Selection
- 6. Age for Direct Recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad-hoc* or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on *ad-hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment.—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION : (i) Should be a Matriculate or its equivalent from recognized Board of School Education/Institution.

(ii) Must possess valid driving licence for the plying of heavy/light vehicles in Hilly terrain.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATION(S).**—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.—*Age* : Not Applicable. *Education Qualification* : Yes, as prescribed against Col. No. 7 above.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(i) 80% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.

(ii) 20% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Cleaner-cum-Conductor/Helper having five years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered if any in the grade.

For the purpose of promotion a combined seniority of Cleaner-cum-Conductors/Helpers based on the length of service without disturbing their *inter-se-seniority* shall be prepared:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that persons who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account

towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. Mechanical, HP PWD and Manager/Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing Authority Passing of practical test shall be mandatory.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Driver in _____ (Name of the Department) will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) **POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.—**The HOD of the concerned Department after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 7910/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). An amount of Rs. 240 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The HOD of the concerned Department will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority *i.e.* HOD of the concerned Department.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority *i.e.* HOD of the concerned Department from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7910/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 240/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over . The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of persons or post (s).

ANNEXURE “B”**Form of contract/agreement to be executed between the Driver and the Government of Himachal Pradesh through _____(Designation of the Appointing Authority)**

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ Between Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Driver on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Driver for a period of 1 (one) year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7910/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Driver will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Driver. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Driver will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over.

The woman candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER SOLAN DISTRICT, SOLAN (H.P.)

ORDER

Solan, 26th November, 2010

No. MA/20-4/99.—Whereas it has been felt expedient to streamline & improve the traffic arrangement on the restricted portion of the Mall Road Solan i.e. Old Bus Stand to DC Office Chowk by way of declaring this portion as No Parking Zone.

Hence, in view of the above in partial modification of this office order of even number dated 07-12-2009 and in exercise of the powers vested in me under Section 115 & 117 of the Indian Motor Vehicle Act, 1988 I, Amar Singh Rathore, IAS District Magistrate Solan declare the stretch of the Mall Road Solan from Old Bus Stand to D C Office Chowk as No Parking Zone for all kinds of vehicles with immediate effect.

By order,
AMAR SINGH RATHORE,
District Magistrate, Solan.

No. TCP-F (6)-10/2001
 Government of Himachal Pradesh,
 Town & Country planning Department

From

The Principal Secretary (TCP) to the
 Government of Himachal Pradesh.

To

1. The Director,
 Town & Country Planning Deptt.,
 Himachal Pradesh, Shimla-9.
2. All the Deputy Commissioners in
 Himachal Pradesh.
3. The Chairman,
 Special Area Development Authorities,
 Hatkoti, Sarahan (Shimla), Kufri, Shoghi, Kandaghat, Barog, Jabli, Paonta
 Sahib, Baba Balak Nath Ji, Pong Dam, Khajjiar, Bharmour, Pangi (Killar),
 Chamera, Una, Pandoh, Solang, Rohtang, Reckong Peo, Kaza, Keylong,
 Tabo and Udaipur.

Dated Shimla-2

27-9-2002

Subject: Cabinet decision regarding raising the number of storeys in case of Residential, Hotel, Commercial, Public and Semi Public buildings in Other Areas of the Planning area/Special Planning Area of the State.

Sir,

The Cabinet in its meeting held on 9-7-2002 has taken various decision as circulated *vide* Notification No. TCP-F (5)-10/2001 dated 22-8-2002. One of the decision *i.e.* raising of limit of number of storeys in the case of construction in other planning areas/special planning areas of the State for Residential, Hotel, Commercial, Public/Semi Public buildings the limit of number of storeys conveyed *vide* letter No. HIM/TP/PJT/Earth Quake/2001-Vol-I dated 19-4-2001 and TCP-F (5)-10/2001 dated 15-12-2001 and dated 2-2-2002 was considered and it has now been approved by the Government to allow construction in other planning areas/special planning areas of the State, the construction, development of land and sub-division of land shall be regulated in\ the following manners:

1. Development permission :		
(a)	Planning permission within Municipal Corporation limit.	The Commissioner, Municipal Corporation.
(b)	Within Municipal Council or Nagar Panchayat Area.	The Executive Officer of the Municipal Council or Secretary, Nagar Panchayat concerned.
(c)	Within the Special Area Development Authority.	The Chairman, Special Area Development Authority concerned.
(d)	Beyond Municipal Corporation/Nagar Panchayat/Special Area Development Authority Area.	The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh.
2.	Landuse	All uses that is residential, commercial, public and semi-public purposes etc.
3.	Minimum plot size	
(a)	Residential	150 Square meters.
(b)	Hotel	1000 Square meters

(c)	Other landuses	250 square meters
4.	Maximum number of storeys	
(a)	Residential	4+ Parking floor wherever feasible.
(b)	Hotel and Public/semi-Public purpose	4+ parking floor mandatory. Shortfall in parking floor, if any, shall be met out in open space over and above the set backs.
5.	Maximum Floor Area Ratio	
(a)	Residential and Commercial	1.75
(b)	Hotel	1.75 subject to maximum plot/coverage of 40%. Minimum 10.00 meters front set backs and minimum 5.00 meters set back on other sides.
(c)	Public and semi Public purposes	2.00 subject to minimum 7.50 meters front set back and minimum 2.50 meters set back on other sides.
6.	Maximum building height	
(a)	Residential	
	(i) Without parking floor	16.50 meters (including 2.50 meters maximum height of slopping roof).
	(ii) With parking floor	18.80 meters (including 2.50 meters maximum height of slopping roof and 2.30 meters height of feasible parking floor).
(b)	Hotel and public/semi-public purposes	18.80 meters (including 2.50 meters maximum height of slopping roof and 2.30 meter height of mandatory parking floor).
7.	Maximum width of path/road	
(a)	Residential	
(i)	For sub-division of land having plots more than five in number.	5.00 meters
(ii)	Otherwise for sub-division of land having plots less than six in number (including pedestrian walkways).	3.00 meters
(iii)	Hotel and public/semi-public purposes.	5.00 meters
8.	Reconstruction	(g) Permissible subject to the condition that plinth area and number of storeys on old lines shall remain the same as were existing earlier. (ii) Any addition if required shall be allowed to the extent of 20% of existing built up area of ground floor subject fulfillment of other norms of these regulations.
9.	Change of landuse	Permissible.
10.	Sub-division of land	Permissible.

Note: Planning permission shall be granted keeping in view the general provisions contained in at Annexure-A.

Yours faithfully,
Sd/-

Principal Secretary (TCP) to the
Government of Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2 27-9-2002

Endst. No. As above

GENERAL REGULATIONS

The following provisions shall be applicable in all areas where no specific mention is made, namely:

1. Demarcation from revenue authority shall be mandatory.
2. Maximum acceptable slope for development 450.been prepared.
3. Maximum height of plinth level 4.00 meters.
4. Height of parking floor shall be 2.30 meters parking floor and it shall be over and above the permissible Floor Area Ratio limit.
5. In case space as per requirement for parking is available in open over and above the set backs, condition of parking floor shall not be insisted.
6. Minimum and maximum height of floor shall be 2.70 and 3.00 meters respectively (for all uses) 25% variations in floor heights if required for specific functional requirement of an activity shall be permissible with restriction of overall height of the structure.
7. Height of sloping roof zero at eaves and maximum 2.50 meters at center.
8. Building along highway falling within the Special Area limits shall have the following mandatory provisions to have harmony with the surrounding environment and hill architecture:—
 - i. Sloping roof with slates, CGI Sheets painted in Maroon or green colour.
 - ii. 0.24 meters wide Facia with CGI Sheet painted in maroon or green colour.
 - iii. Façade rendered preferably in stone or slate cladding. In case of non availability of these materials, with alternative material by giving same touch.
 - iv. Minimum 2.00 meters wide arcade in front of shops construction in a row.
 - v. Building shall be completed/covered with roof within stipulated period failing which penalty shall be imposed.
9. Construction in terraces shall be allowed to have a provision of storeys as permissible subject to fulfillment of Floor Area Ratio provision.
10. 1/3rd area of the top floor shall be allowed as open terrace wherever sloping roof is provided.
11. Set backs:
 - i. Minimum front set backs from the line of controlled width of Highways and other PWD scheduled roads falling within the planning area limits/special planning area limits (excluding the land included in the inhabited sites of any village as entered and demarcated in the revenue record or on sites in Municipal notified or town area that are already built-up) shall be 3.00 meter.
 - ii. Minimum front set back from non scheduled roads and Municipal roads shall be 3.00 meter.
12. For the plots abutting highways, bye-pass and other PWD scheduled roads, No Objection Certificate from Himachal Pradesh Public Works Department shall be mandatory as per Annexure-B attached.
13. Maximum hill cut of 3.50 meter height shall be permissible.
14. Submission of structural design of the building at the time of submission of planning permission cases and structural stability certification on its completion shall be mandatory.
15. Competency for preparation of structural design and its certification:—

(i)	For residential building to be constructed/completed on plot upto 500 square meters and upto three storeys or 11.00 meter height.	Registered Architect.
(ii)	For building to be constructed/completed on plot upto 500 square meters and upto five storeys or 16.00 meter height.	Graduate Civil Engineer having minimum 3 years experience in Engineering structure practice with design and field work.

16. Checking by the concerned department that is Town and Country Planning/Nagar Nigam/Nagar Parishad/Nagar Panchayat/Special Area Development Authority at plinth level and at every floor level shall be mandatory.

17. Building shall not be put to use prior to issue of completion certificate by the department in areas falling outside Municipal Corporation/Nagar Parishad/Nagar Panchayat but within Planning Area.

18. Issuance of No Objection Certificate for water supply and electricity connection:

- (i) Temporary—At Plinth level
- (ii) Permanent—On Completion of dwelling unit/floor/whole building

19. Any No Objection Certificate issued by the department shall be liable for withdrawal on breach of terms and conditions of references of the issuance of such No Objection Certificates and undertaking to this effect shall be rendered by the applicant.

20. No Objection Certificate from the Himachal Pradesh State Electricity Board shall be obtained and attached with the application seeking planning permission as per Annexure "C" attached.

21. Minimum permissible distance between two blocks constructed on a plot shall be 5.00 meter.

22. No development shall be permissible on land having buildable width less than 5.00 meter.

23. Minimum size of the booth/shop shall be 2.50x3.50 meters/3.00x6.50 meters respectively which may be relaxed in planned commercial area.

24. Minimum permissible distance of construction from the circumference of a tree/boundary of Forest shall be 2 meter/5 meter respectively.

25. Reconstruction on old lines/new construction on vacant sites in the pockets having maximum built up area shall be allowed with the prior recommendation of Director, Town and Country Planning to the extent of maximum four storeys+one parking floor provided site abuts minimum 5.00 meter wide street and adhering to set backs regulation except core area.

26. Construction on sandwich plots shall be permissible as per existing building lines.

27. No construction shall be permissible above vision line (1.50 meter) on valley sides of highways/major roads.

28. 25% of the area for development shall be kept for parking in planned commercial complexes.

29. In new sub division of land:

(i)	Minimum width of vehicular access if number of plots is above five.	5.00 meters (with cul-de-sac) at the end.
(ii)	Minimum width of pedestrian links to smaller cluster of plots not exceeding five in number	3.00 meters wide.

(iii)	Minimum area for open/green space for the scheme having more than five plots.	10% of the scheme area.
(iv)	Minimum area for soakage pit etc. (irrespective of number of plots)	5% of the scheme area

30. Maximum number of storeys on vacant land/plot located in the bazaar area:—

(i)	Plot abutting path 3.50 meters wide and above.	Three storeys
(ii)	Plot abutting upto 3.00 meters wide path.	Two storeys

31. Not more than three dwelling units per floor shall be permissible in residential building constructed on plot having an area upto 250 square meters. For plot measuring more than 250 square meters one additional dwelling unit for every additional 100 square meters area shall be permissible in each floor.

PERMISSIBLE AREA STANDARD/NORMS FOR DIFFERENT PARTS OF A BUILDING SHALL BE AS UNDER:

Habitable room	Minimum floor Area Minimum width	9.50 square meters 2.40 meters
Kitchen	Minimum floor Area Minimum width	4.50 square meters 1.80 meters
Bathroom	Minimum floor Area Minimum width	1.80 square meters 1.20 meters
W.C.	Minimum floor Area Minimum width	1.10 square meters 0.90 meters
Toilet	Minimum floor Area Minimum width	2.30 square meters 1.20 meters
Corridor	(i) For Residential (ii) For other uses.	1. 0 meter wide minimum 1.20 meter wide minimum
Stair	(i) For residential (ii) For Hotel/Flats/Hostel/Group Housing/Education Institution like School, College etc.	1.0 meter wide minimum 1.50 meter wide minimum
	Auditorium/Cinema Hall.	2.00 meters minimum
Width of treads without nosing	For residential	25 Cente meters minimum for internal stair case.
	For other uses	30 Cente meters minimum for internal stair case.

	For residential	19 Cente meters maximum of numbers maximum is flight).
Height of riser	For other uses	15 Cente meters maximum numbers maximum is flight).
Spiral Stir Cases	In commercial building of three or more storeys. Provision of Spiral stair cases not less than 1.50 meters die with adequate head height other than regular stair case shall be permissible as fire escape in addition to regular stair cases.	
Openings	For sufficient air and light, windows and ventilators provided should have minimum area equivalent to 1/6th of floor area.	
Balcony Projections	1.20 meter wide balcony complete open at two storeys with restriction of 50% of building frontage where minimum front set back is 3.00 meter shall be permissible.	

ANNEXURE-B**NO OBJECTION CERTIFICATE FROM COMPETENT HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT AUTHORITY**

The Department of Himachal Pradesh Public Works has no objection on carrying out any development on land bearing khasra No.----- of revenue village/mohal----- abutting National Highway/State Highway/Scheduled road----- by the owner Sh./Smt.----- resident of----- will respect to provision of Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 19 in this behalf as shown in the site plan.

Seal Competent Authority of Himachal Pradesh Public Works Department.

ANNEXURE-C**NO OBJECTION CERTIFICATE FROM COMPETENT AUTHORITY OF THE HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD**

The Himachal Pradesh State Electricity Board has no objection on carrying out any development on land bearing khasra No.----- of revenue village/mohal----- under the----- resident of Sh/Smt.----- with respect to provisions of Indian Electricity Rules, 1956 in force in this behalf.

Seal Competent Authority of Himachal Pradesh State Electricity Board.